गंभीर हो रही है जलवायु परिवर्तन की स्थिति

भारत डोगरा

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार वायुमंडल में ऊर्जा-उत्पादन से जुड़ा कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन वर्ष 2010 में इतिहास में सबसे अधिक 30.6 गिगाटन हुआ। वर्ष 2008 में यह आंकड़ा 29.3 गिगाटन था। अर्थात इन दो वर्षों के दौरान कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में 1.3 गिगाटन की वृद्धि हुई। गौरतलब है कि 1 गिगाटन मतलब 10^9 (10 अरब) टन होता है।

विश्व स्तर पर आम सहमति बनी है कि वर्ष 2050 तक तापमान वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए यह ज़रूरी माना गया है कि ग्रीनहाउस गैसों की कुल वृद्धि को कार्बन डाईऑक्साइड के रूप में नापा जाए तो दीर्घकालीन स्तर पर वायुमंडल में इसकी मात्रा 450 अंश प्रति मिलियन (पीपीएम) तक सीमित करनी होगी। वर्ष 2000 में यह स्तर 430 पीपीएम तक तो पंहुच गया था। यदि वर्ष 2020 तक उत्सर्जन को 450 पीपीएम तक सीमित करने का लक्ष्य प्राप्त करना है तो अब मात्र 20 पीपीएम वृद्धि की गुंजाइश बची है। यानि 2000-2020 के बीच मात्र 5 प्रतिशत वृद्धि की गुंजाइश प्रति वर्ष है।

450 पीपीएम उत्सर्जन के लक्ष्य का अर्थ है कि कुल ऊर्जा उत्पादन से सम्बंधित कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन को 32 गिगाटन तक सीमित रखा जाए। जबकि वर्ष 2010 में ही यह 30.6 गिगाटन तक पंहुच गया है। इसका अर्थ है कि वर्ष 2010-2020 के बीच मात्र 1.4 गिगाटन वृद्धि की गुंजाइश है। दूसरे शब्दों में जितनी वृद्धि मात्र 2 वर्षों (2008-2010) में हुई थी, अगले 10 वर्षों में वृद्धि को उतना ही सीमित रखने की ज़रूरत है।

अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि वर्ष 2020 में बिजली उत्पादन से जितना कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन होगा उसका 80 प्रतिशत हिस्सा तो उन बिजली संयंत्रों से होगा जो वर्ष 2011 में स्थापित हो चुके हैं या जिनका निर्माण कार्य चल रहा है।

'विश्व ऊर्जा स्थिति' रिपोर्ट के समन्वयक व अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. फतीह बिरोल ने कहा है कि कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में जो अधिक वृद्धि हुई है व इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश से जो कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन तय हो चुका है, उसके चलते तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

वर्ष 2010 में कानकुन में जलवायु परिवर्तन पर हुई वार्ता में विश्व नेत्तृत्व में इस लक्ष्य पर सहमति बनी थी कि 2050 तक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाए।

डॉ. बिरोल ने चेतावनी देते हुए कहा है, विश्व आश्चर्यजनक हद तक उस उत्सर्जन स्तर के नज़दीक आ गया है जिससे हमें 2020 तक बचना है यदि हम तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना चाहते हैं। 2020 तक दबाव बहुत बढ़ जाएगा। अतः हमें बड़े और निर्णायक फैसले बहुत जल्दी करने होंगे, अन्यथा कानकुन में निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करना बहुत कठिन होगा।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की दिसंबर 2010 में जारी रिपोर्ट के आधार पर वैज्ञानिकों की राय है कि वर्ष 1990 से 2020 के बीच विकसित देशों को अपना उत्सर्जन 25 से 40 प्रतिशत के बीच कम करना होगा। विकासशील देशों ने उनसे 40 प्रतिशत कमी की मांग की है। क्या यह संभव होगा? यदि हम यह देखें कि इस बारे में विभिन्न विकसित देशों द्वारा किए गए वादों की ऊपरी सीमा क्या है तो इस आधार पर वे अधिक से अधिक 16 प्रतिशत की कमी कर पाएंगे, वह भी तब जब वे संधि में किसी खामी का अनुचित लाभ उठाने का कुप्रयास न करें। पर यदि हम उनके वादे की निचली सीमा को देखें और यह मानें कि खामियों के दुरुपयोग की पूरी संभावना है, तो कम होने के स्थान पर विकसित देशों का उत्सर्जन 6 प्रतिशत बढ़ भी

सकता है।

यदि इस स्थिति को ध्यान में रखा जाए व साथ ही विकासशील देशों द्वारा अपना उत्सर्जन कम करने सम्बंधी घोषणाओं को भी ध्यान में रखा जाए तो इस शताब्दी के अंत तक की यह खतरनाक स्थिति उभरती है कि तापमान वृद्धि 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है जबकि भयंकर विनाश लीला से बचने के लिए इसे 1.5-2 डिग्री सेल्सियस के बीच रोकना ज़रूरी माना गया है। ***(स्रोत फीचर्स)***